मजदूरों का अपना कोई देश नहीं होता। दुनिया के मजदूरो, एक हो !

फरीदाबाद मजदूर समाचार

मजदूरों की मुक्ति खुद मजदूरों का काम है। दुनिया को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा।

RN 42233

नई सीरीज नम्बर 12 जून 1989 50 पैसे

रूस-चीन

आजकल आमतौर पर कहा जाता है कि रूस और चीन कम्युनिस्ट देश हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रूस और चीन कम्युनिस्ट देश नहीं हैं। असलियत क्या है ?

कोई व्यक्ति, पार्टी या देश कम्युनिस्ट है या नहीं इसके बारे में तय करने के लिये पहले यह जानना जरूरी है कि कम्युनिस्ट होता क्या है।

कम्युनिस्ट को हिन्दी में साम्यवादी कहते हैं। साम्य माने बराबरी—जो ऊँच-नीच, अमीर-गरीब के भेद मिटाकर बराबरी और भाईचारे के समाज के लिए कोशिश करते हैं उन्हें कम्युनिस्ट कहते हैं।

आज से दस हजार साल पहले दुनिया के हर हिस्से में बराबरी और भाईचारे वाली समाज व्यवस्थायें थी। 5-7 हजार साल पहले वे व्यवस्थायें टूटने लगी। दुनिया के कोने-कोने में मानव समाज के बँटने का सिलसिला चला और आज दुनिया में इक्के-दुक्के स्थान पर ही वे आदिम बराबरी और भाईचारे के छुट-पुट समाज बचे हैं।

मानव समाज के लुटेरों और कमेरों में बँटवारे के बाद से कमेरे लोग बराबरी और भाईचारे के पुराने समाज के फिर बनने की इच्छा रखते रहे हैं। दासों और दस्तकारों-किसानों ने दमन व शोषण से मुक्ती पाने के लिए साम्यवादी समाज के सपने को कई तरीकों से हकीकत में बदलने की कोशिशें की पर उन्हें सफलता नहीं मिली।

आज से ढाई-सौ साल पहले नई-नई मशीनों के निर्माण का एक बवंडर-सा आया। इसने नये किस्म के मेहनतकशों, मजदूरों की धड़ल्ले से पैदाइश शुरू की। नये किस्म का सामाजिक ढाँचा, पूंजीवादी व्यवस्था बनी जिसमें मजदूर लगा कर मंडी के लिये प्रोडक्शन करवाया जाता है। पूँजीवाद के बढ़ने और पुराने सामाजिक ढाँचों के टूटने तथा करोड़ों लोगों के दुख-दर्द ने बराबरी व भाईचारे के समाज की इच्छा को और तीव्र किया।

इच्छा और वास्तविकता, सपने और हकीकत में कोई सम्बन्ध है क्या ? प्रकृति और समाज को समझने की बहुत कोशिशें हुई हैं। इन्हीं कोशिशों में एक कोशिश मानव इतिहास की भौतिकवादी समझ में फलित हुई। इसे मार्क्सवाद कहते हैं। बराबरी और भाईचारे के समाज की हजारों वर्ष की इच्छा को मार्क्सवाद ने पूँजीवाद के उदय और विकास द्वारा सम्भव और आवश्यक बनाना सिद्ध किया। इसने यह भी सिद्ध किया कि साम्यवादी समाज का गठन पूँजीवाद को खत्म करके ही किया जा सकता है तथा मजदूरों में यह करने की क्षमता है। इस समझ को वैज्ञानिक समाजवाद भी कहते हैं और साम्यवादी लक्ष्य के लिये लड़ने वालों को कम्युनिस्ट कहते है। 1848 में कम्युनिस्ट घोषणापत्र के छपने को हम कम्युनिस्ट आन्दोलन की ठोस शुरूआत कह सकते है।

अपने आरम्भ से ही कम्युनिस्ट आन्दोलन ने देशों के भेदों को ठुकरा कर दुनिया के मजदूरों की एकता पर जोर दिया है। ऐसा इसलिए कि किसी एक देश में, कितना ही बड़ा वह क्यों न हो, दमन और शोषण नहीं मिटाया जा सकता। प्रोडक्शन की शक्तियाँ इतनी डेवलेप हो गई हैं कि मानव हित में उनका इस्तेमाल दुनिया के आधार पर ही किया जा सकता है। देशों को तोड़कर विश्व साम्यवादी समाज का निर्माण आज की भौतिक आवश्यकता है। "दुनिया के मजदूरो, एक हो !" ठोस जमीन पर आधारित है।

कम्युनिस्ट आन्दोलन की यह भी एक मूल बात है कि पुलिस-फौज-जेल वाले तन्त्र का जन्म मेहनतकशों को दबाकर रखने के लिए लुटेरों की जरूरत के मुताबिक हुआ है। इसलिये फौज और पुलिस को भंग करके आम मजदूरों को हथियार-बन्द करना कम्युनिस्ट कार्यक्रम का एक बुनियादी उसूल रहा है। 1871 में पेरिस के आम मजदूरों ने हथियारबन्द हो कर पुलिस और फौज भंग की तथा 70 दिन तक हथियारबन्द मजदूरों ने अपनी सत्ता कायम रखी। रूस में अक्तूबर 1917 में हथियारबन्द हो कर आम मजदूरों ने पुलिस-फौज भंग करके अपनी सत्ता कायम की। लेकिन 1918 में ही आम मजदूरों से हथियार रखवाना शुरू करके "लाल" फौज का तन्त्र वहाँ बनना शुरू हो गया था। और जल्दी ही, "मजदूरों के हाथों में जब तक हथियार हैं तब तक ही वे अपने हितों की देखभाल कर सकते हैं" वाली मार्क्स की समझ की सच्चाई सामने आई। निहत्थे मजदूरों की हड़तालों को "लाल" फौज ने तोड़ा और मजदूरों द्वारा बगावत करने पर "लाल" फौज ने उसे कुचला। आज की "लाल" फौज के करम चीन में देखे जा सकते हैं। "मजदूरों की फौज" नाम की कोई चीज नहीं होती— आम मजदूरों का हथियारबन्द होना ही मुक्ती की राह पर बढ़ने की गारन्टी है।

कम्युनिस्ट आन्दोलन की एक बुनियादी बात यह भी रही है कि बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को छोड़ कर सब काम करें और जब तक सबकी जरूरतों को पूरा करने जितना प्रोडक्शन नहीं होने लगता तब तक हर एक को बराबर-बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। मिल कर काम करना और बाँट कर खाना कम्युनिस्ट उसूल है।

इन मोटी-मोटी बातों को देखकर ही कह सकते हैं कि रूस-चीन और उन जैसों में कम्युनिस्ट जैसी मूल चीजें नहीं हैं। रूस-चीन की ऊल-जलूल घटनायें पूँजी के राज्य-पूँजीवादी रूप के संकट की उपज हैं।

कम्युनिस्ट तो मजदूर वर्ग के सचेत संघर्षों के जन्म और विकास के लिए काम करते हैं।

—×—

थॉमसन प्रेस में गरमी

87 में जनरल मैनेजर और उससे जुड़े यूनियन लीडर की छुट्टी के बाद थॉमसन प्रेस के मजदूरों को कुछ राहत मिली ही थी कि मैनेजमेंट ने फिर मजदूरों पर दबाब डालना शुरू कर दिया है।

पूँजीवादी कानून बेशक 240 दिन की बात करता है पर थॉमसन में चार साल से ज्यादा समय से काम करने वाले कैजुअल वर्करों को परमानेन्ट करने के लिये मैनेजमेंट से नई यूनियन ने एग्रीमेंट किया। लटके-झटके खाती यह एग्रीमेंट 15 मई से फिर ठप्प हो गई है। अभी भी चार साल से ज्यादा समय से काम करने वाले 100 से ज्यादा कैजुअल वर्करों को पक्का करना बाकी है। वैसे 65-70 कैजुअल वर्कर और भी हैं जो कानूनन परमानेन्ट होने के हकदार हैं।

अब थॉमसन मैनेजमेंट कह रही है कि वर्कर ज्यादा हैं और काम कम करते हैं इसलिये या तो 200 मजदूर हिसाब ले लें या दो शिफ्टों में काम कर रहे 1700 मजदूर तीन शिफ्ट चलायें। सीधी भाषा में, मैनेजमेंट 30-35 परसैन्ट वर्क लोड बढाने की फिराक में है। इसके लिये मैनेजमेंट की चालें हैं : पिछले साल के 20 परसैन्ट बोनस की जगह इस साल 10.37 प्रतिशत पर अड़ना, 4 साल से अधिक वाले कैजुअलों को परमानेन्ट करना बन्द करना, 2 डिपार्टमेंट बन्द करने का 40 वर्करों को नोटिस देना, बात-बात में वर्करों को सस्पैन्ड करना और ओखला में शिफ्ट किये कम्पोजिंग डिपार्टमेंट से काम चलाने की धौंस देना।

इस समय थॉमसन प्रेस में असली मामला वर्क लोड बढाने का है। मजदूर इसे ध्यान में रखेंगे तो वे मैनेजमेंट से टक्कर ले सकेंगे। थॉमसन के मजदूरों को चौकस रहने की जरूरत है क्योंकि इधर-उधर की करके धोखे से उन पर वर्क लोड बढाने की सम्भावना काफी है।

और थॉमसन प्रेस के ठेकेदारों की तो कहना ही क्या, खुद मैनेजमेंट कैजुअल वर्करों को 625 वाला न्युनतम वेतन देने की बजाय 598 के हिसाब से पैसे दे रही है।

—×—

केल्विनटर में उथल-पुथल

इनसैंटिव स्कीमों और मजदूरों में फूट डाल कर मजदूरों के खून-पसीने पर दिन दूनी रात चौगुनी बढ रही केल्विनेटर कम्पनी की मैनेजमेंट मजदूरों के गुस्से को ठंडा करने के लिये इस समय तिकड़मों का जाल बुन रही है। फूं-फाँ करने वाले कुछ मजदूर जाने-अनजाने मैनेजमेंट के हाथों में खेल रहे हैं और मजदूरों की ताकत को छुट-पुट झगड़ों में बिखेर कर इनसैंटिव स्कीम, कम तनखा और ज्यादा वर्क लोड की समस्याओं से मजदूरों का ध्यान हटा रहे हैं। और मैनेजमेंट तथा लेबर डिपार्टमेंट नये-नये बने लीडरों को नेगोसियेशन के नाम पर चन्दीगढ की सैर करा रही है। इन

हमारे लक्ष्य हैं—1. मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिए इसे समझने की कोशिशें करना और प्राप्त समझ को ज्यादा से ज्यादा मजदूरों तक पहुँचाने के प्रयास करना। 2. पूँजीवाद को दफनाने के लिए जरूरी दुनिया के मजदूरों की एकता के लिए काम करना और इसके लिए आवश्यक विश्व कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के काम में हाथ बँटाना। 3. भारत में मजदूरों का क्रान्तिकारी संगठन बनाने के लिए काम करना। 4. फरीदाबाद में मजदूर पक्ष को उभारने के लिए काम करना।

समझ, संगठन और संघर्ष की राह पर मजदूर आन्दोलन को आगे बढ़ाने के इच्छुक लोगों को तालमेल के लिए हमारा खुला निमन्त्रण है। बातचीत के लिए बेझिझक मिलें। टीका-टिप्पणी का स्वागत है—सब पत्रों के उत्तर देने के हम प्रयास करेंगे।

सम्पर्क—मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, बाटा चौक के पास, एन० आई० टी० फरीदाबाद—121001

हालात में जरूरी है कि केल्विनेटर के आम मजदूर ठंडे दिमाग से काम लें और मैनेजमेंट व लेबर डिपार्टमेंट के जाल को काटने के लिये अपनी समस्याओं को आगे रखें। आम मजदूरों को अभी ही साफ कर देना चाहिये कि कोई भी फैसला तभी माना जायेगा जब आम सभा में विस्तार से विचार करके मजदूरों का बहुमत उसे पास कर देगा। दोहरा दें, 1986-87 के 5 करोड़ 70 लाख रुपये से बढ़ कर 1987-88 में केल्विनेटर कम्पनी का मुनाफा 11 करोड़ 82 लाख रुपये हो गया।

और, 542 से 625 न्यूनतम वेतन गजट में आने पर केल्विनेटर मैनेजमेंट ने कैजुअल मजदूरों को 576 रुपये के हिसाब से अप्रैल की तनखा दी है। इस पर चुप्पी कैसे चलेगी ?

—×—

हिन्दुस्तान वायर में धाँधली

24 सैक्टर की इस फैक्ट्री में 2 हजार मजदूर काम करते हैं पर परमानेन्ट 400 वर्कर ही हैं। ठेकेदारों के तो यहाँ 100 वर्कर ही हैं पर मैनेजमेंट कैजुअल वर्करों की दो कैटेगरी बना रखी हैं। सात-आठ सौ मजदूर 58-दिन वाले कैजुअलों की कैटेगरी में हैं, इन्हें दो महीने होने से पहले ही ब्रेक दे दिया जाता है। 800 दूसरी कैटेगरी के कैजुअल वर्करों को ब्रेक नहीं दिया जाता, 3-4 साल तक लगातार काम करने के बाद इनमें से कुछ को परमानेन्ट कर दिया जाता है। ब्रेक न देने के बदले में मैनेजमेंट इन वर्करों के मामले में सरकारी कानूनों को बेझिझक तोड़ती है। तनखा इन्हें 15-16 तारीख को दी जाती है और बोनस तो इन्हें कभी दिया ही नहीं जाता। इधर तनखा के मामले में मैनेजमेंट ने एक और हरकत की है। 542 की जगह 625 वाले न्यूनतम वेतन को अप्रैल की तनखा देते समय मैनेजमेंट ने 58-दिन वालों को तो दे दिया पर लगातार कैजुअलों को 542 के रेट से ही पैसे दिये।

हिन्दुस्तान वायर के परमानेन्ट मजदूरों की तनखायें भी बहुत कम हैं। कैंटीन का खाना बेकार है, कैंटीन वर्करों का और भी बुरा हाल है। सब कैजुअलों से मैनेजमेंट मशीनें चलवाती है जिससे ऐक्सीडैंट बहुत होते हैं।

इन हालात को बदलने के लिये पहले कदम के तौर पर हिन्दुस्तान वायर के मजदूरों को परमानेन्ट-लगातार कैजुअल-58 दिन वाले कैजुअल-ठेकेदारों के वर्कर जैसे भेदों को छोड़ कर संगठित होना होगा।

—×—

मजदूर आन्दोलन की समस्यायें

भिलाई की खदानों से कुछ सबक और सवाल

1977 में भिलाई स्टील प्लान्ट की दल्ली राजहरा स्थित लोहा खदानों के ठेका मजदूरों ने एक बहुत महत्त्वपूर्ण संघर्ष लड़ा। जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता सम्भालते ही पहली गोलियाँ दल्ली राजहरा के ठेका मजदूरों पर बरसाई थी। पुलिस की गोलियों से दर्जन-भर स्त्री और पुरुष ठेका मजदूर मारे गये थे।

ठेका मजदूरों को भी बोनस मिलना चाहिये की माँग को उठा कर इन्टक और एटक यूनियनों द्वारा हड़ताल शुरू करवाना और फिर बिना कुछ हासिल किये हड़ताल खत्म करने की घोषणा से भड़क कर आठ हजार स्त्री-पुरुष ठेका मजदूरों ने इन्टक और एटक को ठुकरा दिया था। हड़ताली मजदूरों द्वारा संघर्ष की नई राह तलाशने और उस पर दृढ़ता से आगे बढ़ने पर एक तरफ जहाँ उन्हें पुलिस की गोलियाँ तक झेलनी पड़ी वहीं मजदूरों की एकता-संघर्ष-कुर्बानी रंग लाई। दल्ली राजहरा खदानों के ठेका मजदूरों ने 1977 की हड़ताल से अपने लिये रोजगार की गारन्टी और वेतन में चार गुणा बढ़ोतरी हासिल की। बाद के इन 10-12 वर्षों में मजदूरों से उस जीत के फल छीनने की पूँजी के नुमाइन्दों ने कई कोशिशें की हैं पर अब तक मोटेतौर पर वे फेल हुये हैं। मई अंक जब छप रहा था तब मध्य प्रदेश से हमें एक मित्र का खत मिला। पत्र में भिलाई स्टील मैनेजमेंट द्वारा दल्ली राजहरा की खदानों के ठेका मजदूरों पर एक नये बड़े हमले की जानकारी थी। इधर अखबारों में भी इस बारे में कुछ चर्चा हुई है। विजयी ठेका मजदूरों को ठिकाने लगाने और पूँजी के हितों को बढ़ाने के लिये मैनेजमेंट कई सालों से लोहा-पत्थर खदानों में पूर्ण मशीनीकरण की फिराक में है। भिलाई स्टील से जुड़ी रूसी सरकार भी ठेका मजदूरों और उनसे जुड़ी राजनीति के सिरदर्द को खत्म करने तथा अपनी मशीनें बेचने के वास्ते पूर्ण मशीनीकरण के लिये दबाव डालती रही है। लेकिन ठेका मजदूरों के लीडर ने दाव-पेचों में अब तक पूँजी के नुमाइन्दों की चलने नहीं दी। पूर्ण मशीनीकरण की स्कीम के मुकाबले लीडर ने अर्ध-मशीनीकरण की स्कीम रखी और दलालों के खेल में पूर्ण मशीनीकरण वालों को पीट दिया। पूर्ण मशीनीकरण के पक्षधर अब धक्के से अपनी स्कीम थोप रहे हैं।

इधर तस्वीर कुछ ऐसी बनी है :—प्रधानमंत्री ने पहली मई को भिलाई में भीड़ जुटा कर 21 वीं सदी में जाने के लिये मशीनीकरण का गुणगान किया। रूसी पूँजी के पक्षधर मशीनीकरण की प्रगतिशीलता के गीत गा रहे हैं और विरोधी मजदूरों से मार-पीट के लिये अपने प्रभाव वाले मजदूरों को उकसा रहे हैं। भिलाई स्टील मैनेजमेंट मजदूरों को **छंटनी नहीं** का आश्वासन दे रही है तथा मशीनें बैठाने का ठेका एक कम्पनी को दे कर विरोधी मजदूरों को इधर-उधर भेज रही है। 20 महीनों में मशीनें बैठाने का 18 करोड़ रुपयों में ठेका लेने वाली कम्पनी ने अदालत से पूर्ण मशीनीकरण के विरोधी मजदूरों के खिलाफ आदेश पास करवा लिया है तथा हजारों मजदूरों के साथ गुण्डों की भरती भी जोर-शोर से कर रही है। डी सी ने इलाके में धारा 144 लगा दी है और आई. जी पुलिस की गाड़ियाँ दौड़ा रहा है। अपनी रोजी-रोटी के लिये चिन्तित आठ हजार ठेका मजदूरों ने 17 मार्च से स्लो डाउन शुरू किया जो कि 5 मई से हड़ताल में बदल गया। मजदूरों ने मशीनों से लदे ट्रकों को रोका हुआ है। नेगोसियेशनें जारी हैं और मजदूरों में आपसी टकराव की सम्भावना को भी बढ़ाया जा रहा है।

इन ठेका मजदूरों ने पिछले 12-13 वर्षों के अपने संघर्षों के दौरान मूल्यवान अनुभव प्राप्त किए हैं जो कि अन्य मजदूरों के भी काम के हैं। आमतौर पर यह मान कर चला जाता है कि कैजुअल या ठेका मजदूर संगठित नहीं हो सकते और संगठित हो भी गये तो वे ज्यादा समय टिक नहीं सकते। दल्ली राजहरा की खदानों के ठेका मजदूरों ने दिखा दिया है कि ठेका मजदूर संगठित हो सकते हैं, लम्बे समय तक डट कर संघर्ष कर सकते हैं और संघर्षों में सफलता भी हासिल कर सकते हैं। आमतौर पर यह भी मान कर चला जाता है कि अनपढ़ और पिछड़े मजदूर कुछ नहीं कर सकते। भिलाई की खदानों में लोहा-पत्थर तोड़ते अनपढ़ और पिछड़े मजदूरों ने दिखा दिया है कि अक्षर ज्ञान के न होने और पिछड़ेपन की बेड़ियों के बावजूद मजदूर संगठित हो कर पूँजी के नुमाइन्दों के दांत खट्टे कर सकते हैं। आमतौर पर यह भी मान लिया जाता है कि मजदूर जाहिल ही रहेंगे, वे नहीं बदलेंगे। दल्ली राजहरा के आठ हजार ठेका मजदूरों और उनके परिवारों ने चन्दा करके स्कूल खोले हैं, एक बड़ा अस्पताल बनाया है और शराब-विरोधी आन्दोलन जैसे कदमों से इस व्यवस्था की बेड़ियों में भी मजदूरों की रचना की झलकें दिखाई हैं। आमतौर पर यह भी मानकर चला जाता है कि मजदूर स्वार्थी होते हैं, वे अपने सिवा किसी की नहीं सोचते। मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में गाँवों में स्कूल खोलकर, कुंये खोद कर, देहाती मेहनत-कशों को संगठित होने में सहायता करके और अकालों के समय राहत के लिए काम करके लोहा-पत्थर खदानों के मजदूरों ने दिखा दिया है कि मजदूर अन्य मेहनतकशों के दुख-दर्द के साथी हैं। दाँव-पेचों का महत्त्व और उनकी सीमायें भी इन मजदूरों के संघर्षों के दौरान सामने आई।

इतने बढ़िया कामों के साथ-ही दल्ली राजहरा की खदानों के मजदूरों ने कुछ ऐसी राह पकड़ी जिसने उनके आन्दोलन को कमजोर किया है और पूँजी के खिलाफ मजदूर वर्ग के संघर्ष में वे अपनी क्षमता के मुताबिक योगदान नहीं दे पाये हैं। हमारे विचार से मजदूरों के इस आन्दोलन की सबसे बड़ी कमजोरी वह नजरिया है जिसके तहत भिलाई स्टील के परमानेन्ट मजदूरों के महत्त्व को देखने से इनकार किया गया है। इस आन्दोलन में हावी नजरिया बढ़ती गरीबी के स्तर को ऊँचे होते क्रान्तिकारीपन का मानदंड मानता है। इस दृष्टि से भिलाई स्टील के परमानेन्ट मजदूरों से जान-बूझकर आँखें मूँदी गई। इसके एवज में देहाती गरीबों से सम्बन्ध जोड़ने के प्रयासों ने बेशक मजदूरों की ताकत बढ़ाई है पर सामाजिक वास्तविकता निर्मम होती है। इतिहास की भौतिकवादी समझ की पुष्टि दल्ली राजहरा खदानों के ठेका मजदूरों के आंदोलन के अन्धी-गली में पहुँच जाने में हुई है।

यह सही है कि मजदूरों में भेद हैं। परमानेन्ट-कैजुअल-ठेकेदार के वर्कर या ऊँची और नीची ध्याड़ी वाले भेदों के साथ ही मजदूरों में जाति-धर्म-इलाका-भाषा-नस्ल-लिंग-देश के भेद भी हैं। मजदूरों के बीच मौजूद भेदों को हवा देना पूँजीवादी राजनीति की सोची-समझी नीति है और मजदूर आन्दोलन में यह ऐसी गलती होती है जिससे बहुत नुकसान होता है। मजदूरों के बीच मौजूद भेदों को स्वीकार करना और दुनिया के मजदूरों के हितों की बुनियादी एकता को मानना एक-दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। दुनिया के मजदूरों की बुनियादी हितों पर आधारित एकता तभी ठोस शक्ल ले सकेगी जब हम इतिहास से विरासत में मिले फूट डालने वाले भेदों के खिलाफ सचेत संघर्ष करेंगे। खुशबू और रंगों की भिन्नता तो विश्व मजदूर एकता को सत-रंगी गुलदस्ते की मोहकता देगी।

जीवन की बुनियादी जरूरतों की प्रोडक्शन इस समय भी समाज की गति की धुरी है। समाज के किसी हिस्से का इस प्रोडक्शन में क्या रोल है यह उसके महत्त्व को तय करता है। यह इसीलिये है कि मजदूर वर्ग ही आज वास्तव में क्रान्ति-कारी वर्ग है—यह इसके बावजूद है कि अनपढ़, अनाड़ी, जाहिल अलग-अलग मजदूर या सब मजदूर तक इस समय क्या सोचते हैं। और यह इसीलिये है कि मजदूर वर्ग में भी फैक्ट्री मजदूरों की अगुआ भूमिका है—फैक्ट्री वर्करों के ओवरटाइम के चक्कर और टीवी-मोटरसाइकिल की फिराक में होने से इसमें बुनियादी फर्क नहीं पड़ता (क्रान्तिकारी राह पर बढ़ने की बजाय पूंजीवादी कूड़े-कचरे में हाथ-पैर मारने से मजदूर वर्ग के दुख-दर्द बेशक बढ़ते हैं)। इसलिए दो पैसे फालतू कमाने वाले मजदूरों के कपड़े-लत्तों की चमक-दमक और छिछली बातों से बिदक कर सबसे गरीब लोगों को संगठित करने में रम जाना क्रान्तिकारी विकल्प के निर्माण में हाथ बँटाना कम और इस विकल्प के निर्माण की कठिनाइयों से मुंह चुराना अधिक है। पूँजीवादी व्यवस्था का बढ़ता संकट उथल-पुथल में ढेरों सामाजिक समूहों को लाता है पर पूँजीवाद का विकल्प मजदूर वर्ग ही प्रदान कर सकता है और इसमें फैक्ट्री मजदूरों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। भिलाई की खदानों में इस समय कुछ लोगों की कोशिश यह है कि मजदूर एक-दूसरे के सिर फोड़ें। मजदूर पक्ष का पहला काम ऐसी कोशिशों को फेल करना है। और अगुआओं को लाख अखरता हो पर ठेका मजदूरों का अन्धी-गली में फँसा आन्दोलन पहले कदम के तौर पर भिलाई स्टील प्लान्ट के परमानेन्ट मजदूरों को आन्दोलन में शरीक करके ही आगे बढ़ने की राह बना सकता है। प्रोडक्शन में फैक्ट्री मजदूरों के महत्त्व की वास्तविकता के मुताबिक कदम उठाकर ही पूँजी के मर्मस्थल पर चोट की जा सकती है। संघर्षों से प्राप्त प्रतिष्ठा दल्ली राजहरा के मजदूरों के लिए इस काम को आसान करेगी।

ब्राजिल के स्टील प्लान्ट के 20 हजार मजदूरों की हड़ताल तोड़ने के लिए वहाँ की सरकार को फौज से हमला करना पड़ा, दक्षिण कोरिया के ह्युन्दाई भारी उद्योग के 25 हजार मजदूरों की हड़ताल को तोड़ने के लिए 15 हजार हथियारबन्द पुलिस को हमला करना पड़ा, फ्रान्स के रेलवे मजदूरों की हड़ताल के खिलाफ फ्रांस सरकार ने सेना इस्तेमाल की, पोलैंड में भारी उद्योगों से शुरू हुई हड़तालों की लहर के खिलाफ फौजी शासन लागू करना पड़ा···यूरोपीय मजदूरों की कारों और भिलाई के मजदूरों की स्कूटरों पर न जाकर हमें उनकी ताकत के आधार और क्रान्तिकारी क्षमता को समझना चाहिये। बड़ी फैक्ट्री के मजदूर जल्दबाजी में कदम उठाने को तैयार नहीं होते और ताकतों का हिसाब लगाते हैं जबकि दिवालिया हो रहे दस्तकार-किसान व टटपूँजिये और फुटकर मजदूर अतिवादी फूँ-फाँ के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं। पर इससे कुछ लोगों द्वारा निकाला गया यह नतीजा कि ज्यादा तनखा ले रहे मजदूर क्रान्तिकारी नहीं रहे बिल्कुल गलत है। बड़ी फैक्ट्रियों के महत्त्व के मुताबिक कदम उठा कर दल्ली राजहरा के बहादुर खदान मजदूर भारत में मजदूर आन्दोलन को आगे बढ़ाने में काफी योगदान दे सकते हैं।

स्वत्वाधिकार व सम्पादक शेरसिंह द्वारा आटोपिन झुग्गी, फरीदाबाद से प्रकाशित व अशोक कम्पोजिंग एजेन्सी द्वारा, मानस प्रिंटिंग प्रेस, दिल्ली-110031 में मुद्रित।